

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठाधीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 21 / 2016

अपीलापट

बन्नाम

रेस्पॉन्डेंट्स

राजस्थान राज्य जलिये तहसीलदार सिरोही

बन्नाम जलिये तहसीलदार सिरोही

पुन जयशंकर ओझा जलिये तहसीलदार सिरोही

निवासी पालीव के वांछित एवं

का 10 मी राजस्व प्रसाद पुन

बन्नाम जलिये तहसीलदार सिरोही

पुन जयशंकर ओझा जलिये तहसीलदार सिरोही

पुन जयशंकर ओझा जलिये तहसीलदार सिरोही

निवासी जल तहसील व जिला

सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

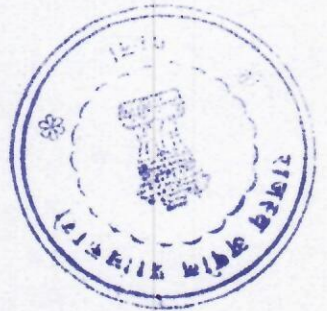
1. श्री जितेंद्रसिंह राठी, विद्वान अभिभाषक अपीलापट
2. सरकारी प्रोकर, रेस्पॉन्डेंट की ओर से

:- निर्यात :-

दिनांक : 4.12.17

अपीलापट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध रेस्पॉन्डेंट के प्रस्तुत कर सहायक जिलाधीश सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2004 बन्नाम मफतलाल वगैरा से पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 को अपस्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉन्डेंट को जलिये समन तलब किया तथा अधिनियम न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलापट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलापट ने अधिनियम न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं खार्चों के विवरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद संख्या 176/1993 श। उक्त वाद में अपीलापट द्वारा मौजा पालीव के खसरा नम्बर 103 रकबा 05 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 104 की 20 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा का अंतर्गोचर था। उक्त वाद में अधिनियम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्लीरेशन संख्या 104 की आराजी का रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर टंकण जूटी से 08 बिस्वा ही दर्ज किया। जिसे रूकस्त कराने हेतु अपीलापट द्वारा अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधिनियम न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जलिये खारिज किया गया है। मातहत अदालत द्वारा टंकण सन्धी उक्त जूटी के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया तथा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर प्रार्थना पत्र खारिज किया। अपीलापट द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर खसरा नम्बर 104 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा होना स्पष्ट अंकित है, किन्तु निर्णय में 20 बीघा दर्ज नहीं किया गया है, जो एक टंकण



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

2



राजस्व अधीन प्राधिकारी पाली
 कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग विभाग
 पाली कानून विभाग
 (डॉ. बजरंगसिंह चौहान)

JK

बाद हस्ताक्षर कर खूले न्यायालय में सुनाया गया।
 यह निर्णय आज दिनांक 4.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर
 न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ
 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2004 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 को
 खारिज की जाती है तथा सहાયक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा
 परिणाम स्वरूप अधीलापट्ट द्वारा प्रस्तुत अधील सारहीन होने से
 किसी प्रकार की विधिक रीटी नहीं पाई जाती है।

निर्णय को रेखांकित करते हुए, बाद विवेचना प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें
 पारित किया गया है। मातहत अदालत द्वारा जैर अधील निर्णय से पूर्व में पारित
 न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई करते हुए जैर अधील आदेश
 मातहत अदालत के समक्ष अधीलापट्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ
 104 रकबा 8 बिस्वा के स्थान पर 20 बीघा 08 बिस्वा दर्ज करवाया जावे। इस पर
 राजस्व बाद संख्या 176/93 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.1994 में खसरा नम्बर
 यह है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा
 किया जाकर अधील अन्दर स्याद श्रमार् की जाती है। अधीलापट्ट का मुख्य अर्जीष
 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार
 गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अधीलापट्ट
 प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अधीलापट्ट के कथनों पर
 कराने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र
 दिनांक 30.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, साथ ही अधील को अन्दर स्याद श्रमार्
 कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 09/2004 में पारित आदेश
 न्यायालय के रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीलापट्ट द्वारा यह अधील सहायक
 उभयपक्ष अभिमाषकाण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ
 न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अधील खारिज करावे।

गया है, जो आदेश पारित होने के 10 वर्ष विनम्ब से पेश किया गया है। अधीनस्थ
 संशोधन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 28.06.2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
 है। मूल बाद में दिनांक 31.03.1994 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके
 न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अधील आदेश पारित किया
 सरकारी श्रेिकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ
 करावे।

08 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 104 का रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा दृक्स्त
 निर्णय एवं हिकी दिनांक 31.03.1994 में खसरा नम्बर 104 की आराजी का रकबा
 अपस्त कराते हुए मूल बाद संख्या 176/1993 सम्पालाल बनम मफलाल के
 विरुद्ध है। अतः अधील स्वीकार करावे एवं मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश को
 हारि हुए भी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है, जो सर्वथा गलत एवं विधि
 सम्बन्धी रीटी है व उसे दृक्स्त करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं